E Learning Study Material
By Prof YADWENDRA SINGH
MAHARAJA COLLEGE ARA
VKS UNIVERSITY ARA BIHAR
BA PART THREE ECONOMICS HONS
PAPER SIX

Tariff Policy in 20th century in USA

बीसवी शताब्दी में प्रशुल्क नीति

1908 ई में प्रशुल्क के प्रति रिपब्लिकन पार्टी की नीति में बदलाव आया। इस पार्टी के एक वक्तव्य के अनुसार - संरक्षण के सच्चे सिद्धान्त का सर्वाधिक अच्छा पोषण ऐसे शुल्कों को लगाए जाने से होता है। जो देश के अन्दर उत्पादन लागत और विदेशों की उत्पादन के लागतों के अन्तरों को एक समान करने के साथ देशी उद्योगों को कुछ तर्कसंगत लाभ प्रदान करते हैं। सन् 1909 ई० के अधिनियम से यह परिवर्तन बिल्कुल स्पष्ट हो गया। 1909 ई० पाइन - आलड्रिक प्रशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत बहुत सी वस्तुओं पर प्रशुल्क दर को एक दम समाप्त कर दिया गया तथा कुछ पर इनकी दरों में काफी कमी कर दी गयी। इस अधिनियम के अनुसार करों की अधिकतम तथा न्यूनतम दरों को भी लागू किया गया।

विभेदात्मक देशों से आने वाली वस्तुओं पर 25 प्रतिशत के अतिरिक्त कर की व्यवस्था की गयी जब पाइन-आलड्रिक अधिनियम लागू किया गया। उस समय तक लोगों में एकाधिकार तथा संयोजन के प्रति घोर असंतोष हो रहा था और लोग समझ रहे थे कि उच्च प्रथुल्क ही इन सारी कठिनाइयों का कारण था। इसके परिणामस्वरूप 1913 में कांग्रेस तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन में डेमोक्रेटिक पार्टी विजयी हुई। राष्ट्रपति उडरो विलसन ने 1913 ई० में एक अधिनियम पारित करवाया जिसके अनुसार प्रथुल्क की दरों में कमी की गयी। राष्ट्रपति क्लीवलैण्ड (Cleveland) के शासन काल से ही डेमोक्रेटिक दल रिपब्लिकन दल के उच्च संरक्षण वाद की कड़ी निन्दा करता आ रहा था और निर्वाचन में राष्ट्रपति विलसन (Woodrow Wilson) की विजय ने एक नवीन प्रथुल्क अधिनियम को अनिवार्य बना दिया। वे संरक्षण के विरोधी थे उन्होंने प्रतियोगी प्रथुल्क (Competitive Tariff) पर जोर दिया था। इस लिए उन्होंने अन्डरउड प्रथुल्क योजना (Underwoods Tariff Scheme) लागू की। इस योजना के अनुसार लोहा, इस्पात, कच्चा ऊन, चीनी और कुछ कृषि वस्तुओं सहित 100 मदों पर प्रथुल्क समाप्त कर दिया गया, 858 मदों पर कम किया गया और 86 मदों पर बढ़ा दिया गया। यह योजना 1921 तक चली